

प्रधान की मनमानी, पंचायत भवन हुआ अप्रासंगिक

(आधुनिक समाचार सेवा)

डॉ०४०४०११ सिंह

प्रतापगढ़। विकास खांडलालगंज के बासपुर (मिशनपुर)गांव के प्रधान की मनमानी से न केवल पंचायत भवन अप्रासंगिक हो गया है बल्कि यह प्रधान का कर्माहृ का हिस्सा बन गया है इस गाँव का प्रधान अशक्त करना गुप्ता पंचायत भवन की मरम्मत जानबूझकर नहीं करवा रहा है। इस पंचायत भवन की छाँ पर वर्षा में लगी कार्ड आज तक नहीं छुड़ाई गई तो इसके शौचालय का दरवाजा भी आज तक नहीं लापाया गया। पंचायत भवन की इस जर्जर अवस्था को प्रधान जानबूझकर इसलिए नहीं ठीक करा रहा है क्योंकि इसमें कुठ बारी पड़ती है वह रहने के लिए दे देता है जिससे उसका लाभ हासिल होता है। शासन का आदेश है कि पंचायत भवन को सूखाजित करके उसमें कुछालय, कंप्यूटर, परिचारिका की जाए जिससे ग्राम पंचायत अधिकारी, रोजगार सेवक/कंप्यूटर ऑपरेटर, परिचारिका आदि यहाँ बैठकर ग्राम पंचायत से संबंधित समस्त कार्यों को शासन की मंथा के अनुरूप निपटाएं लेकिन यह ग्राम प्रधान ने इस



यहाँ आकर बैठता है न ही रोजगार सेवक एवं अन्य कर्मचारी यहाँ आते हैं जिससे ग्रामीणों को ग्राम पंचायत में न हो वह पैसा खारिज करने के लिए उन्हें मरम्मत व रिबोर की शैषणी में प्रस्तावित करके थन खारिज कर रहा है। यहीं नहीं कुछ ग्रामीणों का मृत्यु प्रमाण पत्र, कुरुंद रजिस्टर, पैसन आदि के प्रपत्र पर हस्ताक्षर करवाने के लिए प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी को ढूँढ़ना पड़ता है लेकिन वे उपलब्ध नहीं रहते हैं।

नामांकन के प्रथम दिन कुल 114 लोगों ने पर्चे लियें

विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 के तहत नामांकन के प्रथम दिन कुल 114 लोगों ने पर्चे लिये। जिसके अन्तर्गत 254-फाकामऊ विधानसभा से 09 लोगों ने, 255-सोरांव विधानसभा से 06 लोगों ने, 256-फूलपुर विधानसभा से 10 लोगों ने, 257-प्रापापुर विधानसभा से 14 लोगों ने, 258-हाजिया विधानसभा से 06 लोगों ने, 259-

प्रधान शासन एवं प्रशासन को लेंगे यहाँ आवारा रहने की स्थिति में घृणने हुए आवारा शैषणी को भी वह पशुशालाओं तक रहने के लिए नहीं रखता जिससे किसानों की फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। अपने को संसद एवं दलित वर्ग के कमज़ोर एवं कुछ लोगों को थोस एवं खालीलय देने के लिए बिंदुने वाला नहीं है।

प्रतापपुर एआईएम प्रत्याशी मंजू मौर्य ने क्षेत्र में जनसंपर्क किया

(आधुनिक समाचार सेवा) सरफराज अहमद फूलपुर। शानिपूर्ण एवं पारदर्शी मतदान स्पनन-करने हेतु प्रशासन ने कमर कस ली है। थाना प्रभारी अमित कुमार राय के नेतृत्व में

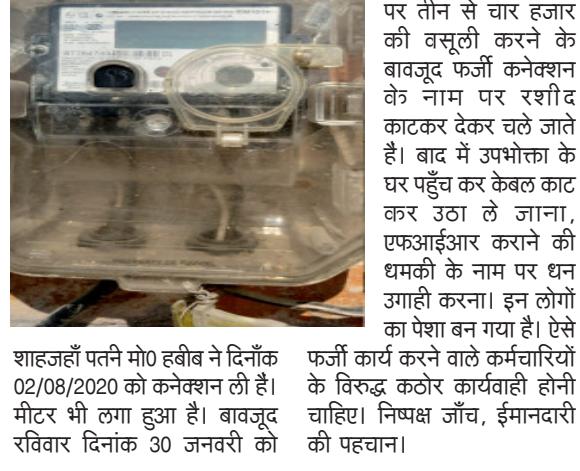


फूलपुर नगर पंचायत के नेहरू बाजार लोचन गंज शुक्राना सिंकंदरा रोड मुबारकपुर रोड बानी बाजार दुनिया गंज दरियापुर कोडापुर कुठुपुर मैलहन आदि गांव में आर ए एक के जाना ने रुट दूटी पुलिया की बैरीकेटिंग ट्रकों ने रोड डाली। अब दूटी सड़क व खुले होल से होकर वाहन दौड़ रहे हैं। जिससे खतरा बलवती हो गया है। इस ओर विभाग चुप्पी साथै बैठा है और किसी बड़े अनहोनी का इंतजार कर रहा है।

उप मुख्यमंत्री के शव मौर्य के खिलाफ उत्तरी अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी

(आधुनिक समाचार सेवा) सरफराज अहमद फूलपुर। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी ने भिड़ी भरी बोरी से दूटी भाग को बैरिकेटिंग कर दिया।

पल्लवी अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल की छोटी बहन है। अनुप्रिया भाजपा के खेमे में है। वहीं पल्लवी पटेल सपा के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। अपनी दल के टिकट के दिन से चुनावी मैदान में है। वह हाट स्टॉप और अपना दल कमेसावादी के गठबंधन के खते में गई है। यहाँ से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के शव मौर्य के टिकट के दिन से चुनावी मैदान में है। अब देखना यह है कि सिराथू की जनता किसके साथ चलती है। सपा और बसपा ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। बसपा ने यहाँ से उपमीदवार बनाया है। सिराथू विधान सभा सीट पर पल्लवी पटेल के आने से मुकाबला रोक दिया है। खास बात यह है कि



शाहजहां पतनी मोहीब ने दिनांक 02/08/2020 की कोनेक्शन ली है। मीटर भी लगा हुआ है। बावजूद रविवार दिनांक 30 जनवरी को पहचाना

यूपी के उप मुख्यमंत्री के शव मौर्य को घेरने की समाजवादी पार्टी ने की रखी है पुरी तैयारी

प्रयागराज। कौशिंबी जनपद की सिराथू सीट पर राजनीतिकों की पलुवी ने अपना दल कमेसावादी की लोग तंग हो गए हैं। उनका कहना है कि शासन की योजनाओं से यह की कार्यशैली से इस ग्राम पंचायत के लोग तंग हो गए हैं। उनका कहना है कि शासन की कोशिश की है। उन्हें शब्दों में कहें तो साधा भाजपा उमीदवार व डिपोर्टी सीएम के शव मौर्य को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। बसपा ने यहाँ से संसदीकृत प्रियांका के मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने अपनी यहाँ अपना उमीदवार घोषित नहीं किया है कौशिंबी की सबसे हाट सीट के जातिगत समीकरण पर नजर डालें तो यहाँ सबसे ज्यादा 57 हजार बासपा से मतदाता है। दूसरे द्यावा ने यहाँ पर मूसिम मतदाता लागत 50 हजार है। इसके अलावा करीब 32 हजार पटेल, 30 हजार यादव, 30 हजार हरिजन, 30 हजार वैश, 20 हजार ब्राटिंग, 18 हजार पाल विरादरी के वोटर हैं। इस तरह से देखें तो सपा ने यहाँ एपोवाइ यानी मूसिम, यहाँ आवारा रहने की सज्जा के देखते हुए यह दांव खेला है। तीनों के मिलाकर देखते होए एक लाख 10 हजार से ज्यादा वोट को सपा ने यहाँ मानकर चल रही है। वहीं अपने पाले में करने की कोशिश में है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राजश कुशवाहा भी सिराथू सीट से मैदान में है। वह जन अधिकार पटी के बैनर देखते होए लड़ रहे हैं। काफी समय तक बसपा में रहे हैं। इसका देखते हुए यह कहा जा रहा है। वार्षिकी मतदाता की गई। इसका वीडियो भी इंटरेस्ट मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद भाजपा के एक और नेता जब डिपोर्टी सीएम का प्रवार करवाए गए तो उनका भी लोगों ने विरोध किया। केशव 2012 में पहली बार सिराथू विधानसभा से ही है।

सकता है कि सिराथू सीट पर इस बार मुकाबला रोक होगा। सिराथू सीट से प्रत्याशी घोषित होने के बाद डिपोर्टी सीएम जबहली बार क्षेत्र में आए तो कुछ महिलाओं ने उनका जोरदार विरोध किया।

विद्यायक बने थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में फूलपुर से सांसद होने पर उन्होंने यहाँ से त्याग पत्र दे दिया था। चुनावी अंकड़ों पर नजर डालें तो 1951 से लेकर 2017 तक हमेशा यहाँ रोक लगाया हुआ है। कभी कांग्रेस तो कभी छोड़ दल, कभी बसपा, सपा और भाजपा ने यहाँ पर अपना परचम लहराया है। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने शीतला प्रसाद को प्रत्याशी बनाया। शीतला 78,621 वोट लेकर विजयी हुए थे। सपा प्रत्याशी वाचस्पति को 52,418 वोट ही मिल पाए थे। 2012 में भाजपा प्रत्याशी के शीतला प्रसाद 57,962 वोट लेकर विधायक बने थे। 2007 में बसपा प्रत्याशी वाचस्पति ने बाजी मारी थी। वाचस्पति को 48,997 मत सपा प्रत्याशी मतेस सोनकर को 26,999 वोट हासिल हुए थे। 2002 में बसपा प्रत्याशी मतदाता सोनकर ने जीत हासिल की थी। उन्हें 33,464 वोट मिले थे। मतदाता से सपा प्रत्याशी शैलेंद्र को हराया था। शैलेंद्र को 29,655 वोट मिले थे।



नैनी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, प्रयागराज

भारत सरकार की कौशल विकास योजना में अगस्त 2021 से प्रारम्भ हो रहे सत्र के लिए निम्नलिखित ट्रेडों में दाखिले के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। ट्रेड प्रवेश योग्यता तथा प्रस्तुत विभिन्न पाठ्यक्रमों की अवधि इस प्रकार है-

क्र०स०	ट्रेड का नाम	ट्रेड की अवधि	योग्यता
1.	कोपा	1 वर्ष	12वीं पास
2.	फिटर	2 वर्ष	10वीं पास
3.	बेसिक कम्प्युटिंग	6 माह	साक्षर
4.	डाटा इंट्री ऑपरेटर	6 माह	10वीं पास
5.	फायर प्रिवेन्शन एण्ड इंडस्ट्रियल सेफ्टी	6 माह	8वीं पास
6.	सेक्योरिटी सर्विस	6 माह	8वीं पास
7.	कम्प्यूटर हार्डवेयर एण्ड एसेम्बली	1 वर्ष	10वीं पास
8.	सर्टिफिकेट इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन	1 वर्ष	10वीं पास
9.	इलेक्ट्रिकल टेक्निशियन्स	1 वर्ष	8वीं पास
10.	रेफरिजरेटर एण्ड एयर कन्डीशनिंग	1 वर्ष	8वीं पास
11.	योगा असिस्टेन्ट	1 वर्ष	10वीं पास
12.</			

सम्पादकीय

आम बजट में वित्त मंत्री ने खपत और रोजगार बढ़ाने पर दिया जोर, जिससे समग्र अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा।

कद्राय वत्त मत्रा नमला सीतरमण ने कोरोना से उबरती अर्थव्यवस्था को गतिशील करने के लिए एक व्यावहारिक और सार्थक बजट प्रस्तुत किया है। इसके लिए राजकोषीय घटे को बढ़ाने से भी कोई संकोच नहीं किया है। व्यापक रणनीतिक प्रविधानों से अर्थव्यवस्था को विभिन्न-चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया है। वित्त मंत्री को विश्वास है कि वित्त वर्ष 2022-23 में व्यापक वैक्सीन कवरेज, आपूर्ति-पक्ष सुधार और नियमों में ढील से विकास को गति मिलेगी। सार्वजनिक निवेश के साथ निजी क्षेत्र का निवेश अच्छी स्थिति में रहेगा। बजट में खेती और किसानों के हितों को उच्च प्राथमिकता दी गई है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के मद्देनजर कृषि में निजी निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिए गए हैं। प्राकृतिक खेती और मांग आधारित खेती को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष घोषणा की गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर की जाने वाली सरकारी खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए एन प्रविधान किए गए हैं। कृषि उत्तरांशों की मार्केटिंग, ब्रांडिंग और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बड़े एलान किए गए हैं। वित्त मंत्री ने बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत व्यय बढ़ाकर आर्थिक गतिविधियों, खपत और नौकरियों के सज्जन को बढ़ावा देने की रणनीति अपनाई है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 7.5 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय का लक्ष्य रखा है। यह जीडीपी का 2.9 प्रतिशत है। बजट में सौर ऊर्जा सेक्टर को लेकर भी बड़ी घोषणा हुई है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए 48 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। किफायती आवास, रियल एस्टेट और निर्माण पर सरकार ने जार दिया है। सरकार चाहती है कि आने वाले वर्षी में भारत विश्व का मैन्यूफैक्चरिंग हब बनकर उभरे। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए वित्त मंत्री ने बजट में मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बड़े एलान किए हैं। श्रम आधारित कृषि क्षेत्र और सूती वस्त्र उद्योगों को बड़े प्रोत्साहन दिए गए हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बजट में पीएलआइ (उत्पादन आधारित

कोरोना से उबरती अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए सरकार ने बजट में खर्च बढ़ाने का सही कदम उठाया है

स्वाधीनता के अमृत काल में प्रतुत नए भारत को गढ़ने का क्या है संकल्प

सामान्य तौर पर बजट के मौसम में अपेक्षाएं बढ़ जाती है कि सरकार लोगों, खासतौर पर मध्यम वर्ग को खुश करने के लिए करों में राहत देंगे। कारपोरेट सेक्टर की लाइंगिंग रहती है कि उन पर टैक्स घटाने की बात होगी। विदेशी निवेशकों को लगता है कि वित्त मंत्री के पिटारे में से उनके लिए भी कुछ कर राहतें निकलेंगी। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट 2022-23 में ऐसा कुछ नहीं रहा। बल्कि कहा जा सकता है कि जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो यह बजट आगामी 25 वर्षों के विकास का खाका प्रस्तुत करता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले दो-तीन दशकों से बजट में यह देखा जा रहा है कि सरकार पूँजीगत खर्च की ओर से स्वयं को धीरे धीरे विमुख करती जा रही है। ऐसा लगता था कि शायद पूँजीगत निवेश का सारा दारोमदार निजी क्षेत्र पर आ गया है। उस पर भी तुर्य यह कि विदेशी निवेश हर कमी की भरपाई कर सकता है, चाहे वह प्रौद्योगिकी विकास हो, रोजगार हो, निवेश हो अथवा निर्यात। लेकिन पिछले लगभग एक दशक से तमाम प्रयासों के बावजूद देश में पूँजी निवेश बढ़ नहीं पा रहा, चाहे वह सार्वजनिक क्षेत्र हो अथवा निजी क्षेत्र। सरकार के सोच में बदलाव हुआ और सरकार ने संरचनागत ढांचा समेत कई क्षेत्रों में पूँजी निवेश करना शुरू किया। पिछले दो वर्षों से कोरोना की मार सह रही अर्थव्यवस्था में एक नई जान फूँकने के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के निवेश को बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही थी, लेकिन कोरोना के कारण राजस्व भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा था जिस कारण सरकार जो पहले से ही गरीबों की बेहतरी की व्यवस्था करने और कोरोना के राहत पैकेज पर खर्च बढ़ा चुकी थी, उसके लिए निवेश के लिए धन जुटाना संभव नहीं हो पा रहा था। परंतु वर्तमान वित्त वर्ष में 9.2 प्रतिशत की वृद्धि दर के चलते जीएसटी प्राप्तियों में भी अच्छी वृद्धि हुई और प्रत्यक्ष करों के राजस्व में भी। इसका पूरा फायदा उठाने हुए चालू वित्त वर्ष में भी पूँजीगत व्यय में वृद्धि हुई है और आगामी वर्ष में भी साढ़े सात लाख हजार करोड़ रुपये खर्च का प्रविधान किया गया है, जो वर्तमान बजट का 19 प्रतिशत है। पिछले तीन दशकों में शायद यह खर्च सर्वाधिक है। इस स्थिति में वित्त मंत्री ने लोकलुभावन नीतियों से परहेज करते हुए 'प्रधानमंत्री गति शक्ति परियोजनाएँ' को तेजी प्रदान करने का प्रयास किया है। इसमें विविध प्रकार के इन्फास्ट्रक्चर के समन्वित विकास का लक्ष्य है, ताकि देश में लाजिस्टिक लागत को कम करते हुए देश की कार्यदक्षता में वृद्धि की जा सके। इसके लिए विभिन्न प्रकार के खर्चों का प्रविधान तो किया ही है, साथ ही लघु उद्योगों, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर, पेयजल के लिए व्यवस्था एवं गरीबों के लिए आवास समेत विविध प्रकार के खर्चों का प्रविधान किया है। यह

मोदी सरकार ने देश के आर्थिक भविष्य को सुधारने पर दिया ध्यान

कारोना सकट के बीच आये एक और आम बजट इसलिए विशेष रूप से उत्तेजनीय है, क्योंकि मोदी सरकार ने देश के आर्थिक भविष्य को सुधारने पर ध्यान दिया, जिसके लिए लोकलभगत योजनाओं के

सभी भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। कहा जा सकता है कि यह बजट लोकलभावन नहीं, बल्कि आगामी 25 वर्षों के विकास पर केंद्रित है। उदयोगों का संरक्षण : भूमंडलीकरण के दौर में संरक्षण एक प्रकार से प्रतिबंधित शब्द हो गया था।

An aerial photograph of a modern highway with four lanes in each direction, separated by a central barrier. The highway is surrounded by lush green vegetation and trees. In the background, there are numerous buildings, suggesting a densely populated urban area. The sky is clear and blue.

www.english-test.net

नाने वाला उदयोग नष्ट हुआ, लेकर्ट्रिनिक उदयोग तो अपने शिश गल में ही मत्यु को प्राप्त हो गया, इसायनिक उदयोग पर भी बुरा भाव पड़ा और लघु उदयोगों की ओर दुर्गति हुई उसे सब जानते ही डब्बयूटीओ यानी विश्व व्यापार गठन में हैं और सतन 40 प्रतिशत

संरक्षण देते हुए टैरिफ को 10 शत से 20 प्रतिशत करने की गा की थी। उसके बाद संरक्षण यह क्रम निरंतर बढ़ता रहा। इनाम काल के दौरान सरकार ने वाहनों ही पूर्व की मेंक इंडियाड ने में बदलाव करते हुए, अपनिर्भर भारत के लक्ष्य को कित किया। जिन क्षेत्रों में वाहनों के कारण सबसे ज्यादा वाहन पड़ा है उनमें से 13 क्षेत्रों को बदल करते हुए उत्पादन से संबद्ध वाहन यार्नी पीएलआई योजना की गई। सेमीकंडक्टर को देश बनाने के लिए पिछले माह 10 डालर के सहयोगी की घोषणा हुई। यह सब देश के उद्योगों संरक्षण के लिए किया गया। इन बजट में भी उस नीति को खरखते हुए सरकार ने विविध एवं उत्पादों के हिसाब से टैरिफ ने की घोषणा की है और कई में जहां पूर्व में देश में उत्पादन के लिए मध्यवर्ती वस्तुओं के बढ़ाए गए थे, उस छूट को आपस लिया है। देश में सौर ऊर्जा के उपकरणों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 19,500 करोड़ रुपयों की विशेष घोषणा भी बजट हुई है। कृषि विकास : हरित वन के समय से जिस प्रकार से रासायनिक खेती को बढ़ावा गया, उससे कृषि उत्पादन तो लेकिन साथ ही किसानों का पर खर्च भी बढ़ा और हमारे पदार्थों में कैटनाशकों समेत वाहन रसायन भी आ गए। पिछले समय से सरकार का जोर यन्मुक्त खेती की ओर है।

बजट में आखिर डिजिटल राह पर तेजी से किस प्रकार से अग्रसर होगी शिक्षा

विश्व अथेव्यवस्था में अब अधिकाश क्षेत्रों में डिजिटल इजेशन का तेजी से उपयोग हो रहा है। साथ ही इसका दायरा निरंतर बढ़ता जा रहा है। इस बीच तकनीक आधारित शिक्षा का तेजी से प्रचार-प्रसार हो रहा है। ऐसी स्थिति में पुरानी शिक्षा पद्धति में परिवर्तन आवश्यक हो गया है। वर्ष 2022-23 के आम बजट में शिक्षा के नवीनीकरण और डिजिटल इजेशन की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। शिक्षा पर होने वाला खर्च जो 2021-22 में 2020-21 की अपेक्षा लगभग छह प्रतिशत कम कर दिया गया था, यानी 99311 करोड़ रुपये से घटकर 93224 करोड़ रुपये रह गया था, उसे 2022-23 के बजट में 6.4 प्रतिशत बढ़ाकर 40828 करोड़ रुपये कर दिया गया है कोरोना के कारण पिछले दो वर्षों से बच्चे स्कूल जाने से विचित हैं। ऊंची कक्षाओं की पढाई अनलाइन होती रही, किंतु स्कूली शिक्षा बुरी तरीफ में रही है।

गए हैं। देश का सभी भाषाओं में डिजिटल एजुकेशन हो सके इसके लिए सरकार ने बजट में सजकता दिखाई है। पहली से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए -एक क्रूस एक टीवी चैनल- योजना का विस्तार किया जाएगा। ऐसे टीवी का प्रसार तेजी से हो पाएगा, विशेषकर गाँवों एवं छोटे शहरों के छात्र शिक्षा के नए पोर्टलों से बहुत लाभान्वित होंगे। युवाओं में कौशल बढ़ाने एवं आजीविका के साधनों के विकास में डिजिटल शिक्षा विशेष लाभदायक साबित होगी। डिजिटल



में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेगा। दृश्यविद्यालय और शिक्षा संस्थान इसके संचालन में सहयोग करेंगे। कृषि शिक्षा के नवीनीकरण और गुणवत्ता में वृद्धि के लिए आधुनिक विषय और तकनीक शामिल किए जाएंगे। कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन किया जाएगा। प्रकृति आधारित और आर्गेनिक खेती को कृषि शिक्षा का अंग बनाया जाएगा। गंगा के किनारे रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती की शुरुआत की जाएगी। सरकार और निजी क्षेत्र के सहयोग से किसानों को डिजिटल सेवाएं प्रदान की जाएंगी। कृषि पदार्थों की ब्रांडिंग का भी विकास किया जाएगा। कृषि उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता दी जाएगी। ड्रोन भी अब किसानों की सेवा में लगाए जाएंगे। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक विद्यालय स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के अध्यापकों के बड़े स्तर पर प्रशिक्षण की आवश्यकता है। साथ ही विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में कंप्यूटर एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए विशेष धन आवंटित करने की भी आवश्यकता है। बजट में जो प्रविधियां किए गए हैं उनमें और वृद्धि

भ्रष्टाचार देश को दीमक की तरह खोखला करने का करता है काम

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में यह जो कहा कि भ्रष्टाचार देश को दीमक की तरह खोला करने का काम करता है उससे किसी के असहमत होने का कई प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। यह एक कटु सच्चाई है कि भ्रष्टाचार देश की तमाम समस्याओं की जड़ है। चिंता की बात यह है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के तमाम उपायों के बावजूद वह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन ऐसी खबरें सामने आती हैं जिससे पता चलता है कि एक ओर जहां रिश्वतखोरी का सिलसिला कायम है वहीं दूसरी ओर बड़े पैमाने पर टैक्स की चोरी भी हो रही है। बड़े-बड़े व्यापारी किस तरह से टैक्स चोरी में लिप्त हैं, इसका उदाहरण है विभिन्न एजेंसियों की ओर से की जाने वाली छापेमारी के दौरान कर चोरी के हैरान करने वाले मामलों का भंडाफोड़ होना। यह ध्यान में रखने की जरूरत है कि टैक्स चोरी का काम भ्रष्ट व्यापारियों और नौकरशाहों की मिलीभगत से ही हो रहा है। भ्रष्टाचार का एक बड़ा जरिया सरकारी ठेके भी बने

A close-up portrait of Prime Minister Narendra Modi. He is wearing his signature grey shawl and glasses. He has a serious expression and is looking slightly to the right. In the background, the Indian national flag is partially visible, along with the Ashoka Chakra emblem on a white wall.

